(घ) इसमे कितने आदिवासी गांव प्रभावित हुए ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) से (घ). गुजरात सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों के गांवो सहित उन गांवो की संख्या की सूचना भेजी है जो या तो हाल ही मे पूर्ण हुई बृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से अथवा उन परियोजनाओं से जिनका निर्माण काफी हद तक हो चुका है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से प्रभावित हुए है । ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

परियोजना का नाम	डूबने वाले गांवो की संख्या (पूर्णत अथवा आंशिक)	डूबने वाले-आदिवासी गावों की संख्या
1	2	3
बृहद		
1. कडाना	46	46
2. पानम	42	34
3. धरोई	44	18
4. वतरक	37	6
5. उकई	170	170
6. दमन गंगा	22	22
मध्यम		
1. छप्परवाडी (दो)	1	..
2. फोफल	1	..
3. अंकलेश्वर मे परियोजना	3	3
4. मच्छनाला परियोजना	10	10
5. वेडी	9	6
6. नारा	2	..
7. घोडाटाड	1	..
8. हर्नव-दो	1	1
9. बलदेवा	3	3
10. पिगुट	1	1
11. कलिंदरी	1	..

(ग) सिंचाई एक राज्य-विषय है और सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है । इसलिए यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वे भूमि के अधिग्रहण और प्रभावित व्यक्तियों को पुनः बसाने के लिये आवश्यक कदम उठाए ।

सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए धन की व्यवस्था भी राज्य सरकारो द्वारा स्वयं की जाती है । राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानो के रूप मे दी जाती है जो विकास के किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा परियोजना से संबंधित नही होती ।

Appointment of Punjabi Teachers in Delhi

6248. SHRI B. S. RAMOOWALIA: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state how many PGT and TGT Punjabi teachers have been appointed in Government Schools in the Union Territory of Delhi in 1977 and what is the plan for 1978?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRIMATI RENUKA DEVI BARAKATAKI): According to information received from the Delhi Administration, no PGT (Punjabi language) was appointed during 1977, because there

was no vacancy. 7 TGT (Punjabi language) were appointed on short term basis. 5 vacancies of TGT (Punjabi language) carried over from 1977 will be filled during 1978. Fresh vacancies of PGT/TGT (Punjabi language) during 1978 will depend upon enrolment in the academic session 1978.

दिल्ली में आवासहीन व्यक्तियों की संख्या

6249. **श्री हुक्म देव नारायण यादव** : क्या **निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में आवासहीन व्यक्तियों की संख्या कितनी है और क्या सरकार ऐसे आवासहीन व्यक्तियों को रिहायशी आवास दिलाने की कोई योजना बना रही है ?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली में बिना मकान वाले लोगों की संख्या के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उन्होंने पुनर्वास कालोनियों में 25 वर्गगज के प्लाटों पर लगभग 20,000 मकान बनाये हैं जिनका आवटन किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लगभग 49,000 परिवारों को 25 वर्ग गज के प्लाट भी दिए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए बड़ी मात्रा में सार्वजनिक आवास का एक कार्यक्रम आरम्भ किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण की विभिन्न आवासीय योजनाओं की सी०एस०पी०/जनता श्रेणियों के अधीन अभी तक लगभग 9000 मकान बनाये गए हैं, जो 7500 अतिरिक्त फ्लैट निर्माणाधीन हैं उनकी वर्ष 1978–79 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है और 8500 अतिरिक्त मकानों के विन्यास नक्शों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और उनके विस्तृत प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

विष्णुपुरी लिफ्ट सिंचाई योजना

6250. **श्री केशव राव धोंडगे** : क्या **कृषि और सिंचाई** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नांदेड जिले में नांदेड के समीप विष्णुपुरी लिफ्ट सिंचाई योजना का 'भूमि पूजन' राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा किया गया था,

(ख) उस समय उस योजना की रूपरेखा क्या थी,

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा योजना के लिये भेजे गये प्रस्ताव का केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन किया था,

(घ) क्या योजना के स्वरूप को बहुत कम कर दिया गया है, और

(ङ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कार्य के लिये सहायता दी थी ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) जी हां महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि विष्णुपुरी लिफ्ट सिंचाई स्कीम का जो लोअर गोदावरी (इस्टपुरी) स्कीम के नाम से भी जानी जाती है, 'भूमि पूजन' राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री द्वारा नवम्बर, 1976 में किया गया था;

(ख) से (घ). राज्य सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को परियोजना रिपोर्ट सितम्बर, 1975 में भेजी थी। इस स्कीम में 52648 हैक्टेयर की सिंचाई लाभ पहुंचाने के लिए 25.5 टी.एम.सी. जल का सफल